

# लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए हमारे निरंतर अभियान में जुड़ें और उसे मज़बूत करें!

कामगार एकता कमिटी और कलवा-मुंब्रा रेलवे यात्री सुरक्षा संघर्ष समिती का आह्वान, अप्रैल-मई 2026

## नागरिकों!

जैसा कि आप में से कई जानते हैं, कलवा-मुंब्रा रेलवे यात्री सुरक्षा संघर्ष समिती का गठन अक्टूबर 2025 में कामगार एकता कमिटी द्वारा किया गया था। उस दिन से लेकर अब तक, हमने कई महीनों तक लगातार एक व्यापक जन-अभियान चलाया है, जिसमें हमने लोकल यात्रियों की परेशानियों के साथ-साथ उनकी मांगों को भी सामने रखा है।

हमने बड़ी संख्या में रैलियाँ आयोजित कीं; नगरसेवकों से लेकर सांसद तक विभिन्न स्तरों के जनप्रतिनिधियों से मिलने का प्रयास किया और कई से मुलाकात भी की। साथ ही डीआरएम से लेकर स्टेशन मास्टर तक रेलवे अधिकारियों को अपने मांग पत्र सौंपे। हमने कई बार स्मरण पत्र भी दिए। हमने अनेक पर्चे (लीफलेट) प्रकाशित किए और हर बार उन्हें स्टेशनों के बाहर, सड़कों पर और यहाँ तक कि घर-घर जाकर वितरित किया।

हम अपने अभियान को मीडिया में भी लाने में सफल रहे। इसमें अक्षराज, मजदूर एकता लहर आदि जैसे अखबार और आर्टिकल 14 और विकल्प वाणी जैसे चैनल शामिल हैं।

हमारी मांगों में बेहतर लोकल सेवाओं से जुड़ी सामान्य मांगें और स्टेशन-विशिष्ट मांगें दोनों शामिल थीं। लगातार प्रयासों के बाद हम कलवा स्टेशन से संबंधित कुछ मांगों को पूरा करवाने में सफल हुए। हालांकि, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हमाल और आपातकालीन चिकित्सा कक्ष जैसी महत्वपूर्ण मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं।

सबसे तात्कालिक मांग उन हजारों यात्रियों के बीच गूंज उठी, जिनके पास काम और पढ़ाई के लिए कार-शेड ट्रेनों में चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारी मांग थी: **“जब तक होम प्लेटफॉर्म नहीं बनता और यात्री कलवा स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, तब तक दीवार न बनाई जाए!”**

ठाणे महानगरपालिका चुनाव के दौरान हमने इस मांग को एक गंभीर मुद्दा बनाया और अब तक दीवार के निर्माण को रोकने में सफल रहे। हालांकि, हजारों दैनिक यात्रियों, उनके परिवारों और जागरूक नागरिकों के समर्थन के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दीवार नहीं बनेगी।

एक बात स्पष्ट है—पूरे मुंबई उपनगरीय लोकल नेटवर्क में बड़े स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। यह एक बड़ा कार्य है और तभी संभव होगा जब हजारों लोग हमारे अभियान से जुड़ेंगे। **हम निम्नलिखित मांगों के लिए इस अभियान को और व्यापक बनाएंगे:**

- हर लोकल ट्रेन में कम से कम 15 डिब्बे होने चाहिए (वास्तव में, RDSO [भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन] ने 2008-2009 में ही 18-कार लोकल ट्रेनों के लिए तकनीकी स्वीकृति दे दी थी!)



विकल्प वाणी वीडियो देखने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस लिंक पर जाएं:  
<https://www.youtube.com/watch?v=hAVzSSqBxjQ>

- लोकल ट्रेनों की आवृत्ति (frequency) कम से कम 50% बढ़ाई जानी चाहिए। यह नए सिग्नलिंग सिस्टम के माध्यम से आसानी से संभव है, जैसा कि मेट्रो ट्रेनों के लिए किया जाता है। MRVC (मुंबई रेलवे विकास निगम) ने आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का प्रस्ताव दिया था ताकि ट्रेनों के बीच का अंतराल 2.5 मिनट तक घटाया जा सके; हालांकि परियोजना को 2019 में MUTP-3A के तहत मंजूरी मिली थी, काम आगे नहीं बढ़ा। बढ़ते भार को संभालने के लिए पर्याप्त रेलवे कर्मचारियों—जैसे मोटरमैन, गार्ड आदि—की भर्ती की जानी चाहिए।

**हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि इन मांगों को जीतने के लिए, जिनसे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा, आप में से हर एक को हमारे साथ जुड़ना होगा और अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना होगा:**

- सभी स्तरों के जनप्रतिनिधियों से मिलें और उनसे इन मांगों को उठाने की मांग करें।
- अपने संगठनों, यूनियनों, कॉलोनियों, सोसायटियों, भजन मंडलों आदि में पर्चों का वितरण करें।
- इस अभियान की मांगों पर नाटक, गीत, वीडियो, रील्स तैयार करें। उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल बनाइए।
- यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से इस अभियान को व्यापक रूप से फैलाएँ, इसे वायरल बनाएं।

**यह पूरा अनुभव हमें आज के लोकतंत्र के बारे में कड़वी सच्चाइयाँ सिखाता है:**

- आम नागरिकों के पास अपनी मांगों को जनप्रतिनिधियों तक आसानी से पहुँचाने का कोई स्थापित माध्यम नहीं है। उनसे मिलना और अपनी बात रखना बेहद कठिन है।
- अपनी आवाज उठाने के लिए हमें एकजुट होकर समय, पैसा और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
- अधिकारी हजारों नागरिकों की आवाज सुनने और उनकी वैध जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- चुनाव से पहले वादे करने के बावजूद, चुनाव के बाद वे अपनी पार्टी के “हाई कमांड” के अनुसार काम करते हैं और वादे भूल जाते हैं।
- दूसरी ओर, बड़े पूंजीपति—जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ की होती है—को अपने आदेश मनवाने के लिए किसी प्रतिनिधि से मिलने की भी जरूरत नहीं होती। उनके कर्मचारी केवल “निर्देश” देते हैं और उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि बड़े पूंजीपति ही इन बड़ी पार्टियों को वित्तपोषित करते हैं और सरकार द्वारा बनाई और लागू की गई नीतियों और कानूनों के माध्यम से अपना “निवेश” वापस लेते हैं।

**सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अपनी समस्याओं का समाधान करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमें पूंजीपतियों के शासन को बदलकर मज़दूरों के शासन की स्थापना के उद्देश्य से संघर्ष करना होगा!**

यही हमारा उद्देश्य है! हमारे संगठनों से जुड़ें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेन सेवाओं में सुधार के अभियान का हिस्सा बनें!

**संपर्क:** 7208388230 / 9820119317



कलवा-मुंब्रा रेलवे यात्री सुरक्षा संघर्ष समिती  
के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए QR कोड  
स्कैन करें